



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 458]  
No. 458]

नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 12, 1985/अश्विन 20, 1907  
NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 12, 1985/ASVINA 20, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

बीमा

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर, 1985

अधिसूचना

भारतीय जीवन बीमा निगम, श्रेणी 1 अधिकारी

(सेवा के निबन्धनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1985

मा० का० नि० 794(घ) :- केन्द्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 48 की उपधारा (2) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय जीवन बीमा निगम के श्रेणी 1 के अधिकारियों (प्रबन्ध निदेशकों से निम्न) की सेवा के कतिपय निबन्धनों और शर्तों का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना :- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम, श्रेणी 1 अधिकारी (सेवा के निबन्धनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1985 है।

(2) ये 1 अक्टूबर, 1983 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

(3) ये नियम, जब तक कि किसी संविदा के निबन्धनों द्वारा अन्यथा उपबंधित न हो, भारत में निगम के प्रत्येक पूर्णकालिक (वेतन-भोगी) श्रेणी 1 अधिकारी को लागू होंगे।

(4) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी, राजपत्र में इन नियमों के प्रकाशित होने की तारीख से सोम वित्त के भीतर यदि कोई श्रेणी 1 अधिकारी निगम को लिखित सूचना देता है, जिसमें वह इन नियमों के ऐसे प्रकाशन की तारीख से उसके उपबन्धों से शासित होने का अपना विकल्प अभिव्यक्त करता है, तो निगम, आदेश द्वारा, ऐसे अधिकारी को उक्त तारीख से उक्त नियमों द्वारा शासित होने की अनुज्ञा दे सकता है।

2. परिभाषाएं :- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(क) "अधिनियम" से जीवन बीमा अधिनियम, 1956 (1956 का 31) अभिप्रेत है :

(ख) "श्रेणी 1 अधिकारी" से भारतीय जीवन बीमा निगम का (प्रबन्ध निदेशकों से भिन्न) श्रेणी 1 पद पर कार्य

कर रहा का कर्मचारी अभिप्रेत है और इसके अस्तित्व वह व्यक्ति भी है जो अधिनियम के अधीन, नियत बिन को, ऐसा कर्मचारी हो गया है और इस रूप में कार्य कर रहा है;

(ग) "कर्मचारी बृंद" विनियम, से भारतीय जूनियर बीमा निगम (कर्मचारी बृंद) विनियम, 1960 अभिप्रेत है;

(घ) ऐसे बच्चों और पत्नी का जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है, किन्तु जो कर्मचारी बृंद विनियमों में परिभाषित हैं वही अर्थ है जो कर्मचारी बृंद विनियम में है।

3. श्रेणी 1 के अधिकारियों की सेवा की शर्तें :- कर्मचारी बृंद विनियम में किसी बात के होते हुए भी इन नियमों में सम्मिलित विषयों के सम्बन्ध में श्रेणी 1 के अधिकारियों की सेवा के निबन्धन और शर्तें एवं नियमों में इसके पश्चात् अतिरिक्त उपबन्धों के अनुसार विनियमित होंगी।

4. श्रेणी 1 अधिकारियों के वेतनमान :- श्रेणी 1 अधिकारियों के वेतनमान निम्नलिखित होंगे :-

श्रेणी 1 अधिकारी :

- |   |   |
|---|---|
| 1. (i) क्षेत्रीय प्रबन्धक/केन्द्रीय कार्यालय में विभागों के प्रमुख। | (क) सामान्य वेतनमान : 3725-125-4350 रु० |
| (ii) मुख्य इंजीनियर/मुख्य वास्तुविद                                 | (ख) ज्येष्ठ वेतनमान 4100-125-4600 रु०   |

टिप्पण :

- (1) केन्द्रीय कार्यालय में किसी विभाग के भारसाधक के रूप में पदस्थ ज्येष्ठ वेतनमान के अधिकारी कार्यकारी निवेशक के रूप में पदभारित होंगे।
- (2) यद्यपि सामान्यतया केन्द्रीय कार्यालय में विभागों के प्रमुख, क्षेत्रीय प्रबन्धकों के काडर में से मिये जायें तथापि अर्थात् इन काडर में इन पदों को भरने हेतु उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध न हों वहाँ उन्हें उप क्षेत्रीय प्रबन्धकों/वरिष्ठ मण्डल प्रबन्धकों और केन्द्रीय कार्यालय के मजिस्ट्रो/बीमाकर्ता/लेखाकारों के काडर में से लिया जा सकेगा तथा उन्हें प्रमुख भारसाधक के रूप में पदभारित किया जाएगा।

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| 2. (i) उप क्षेत्रीय प्रबन्धक/वरिष्ठ मण्डल प्रबन्धक और केन्द्रीय कार्यालय के सचिव/बीमाकर्ता/लेखाकार।<br>(ii) उप मुख्य इंजीनियर/उप मुख्य वास्तुविद।  | } 3245-110-3685-115-3800 रु० |
| 3. (i) मण्डल प्रबन्धक और क्षेत्रीय कार्यालयों के सचिव/बीमाकर्ता/लेखाकार/केन्द्रीय कार्यालय के उप सचिव (लेखापरीक्षा और निरीक्षण)/उप सचिव/उप बीमाकर्ता/उप लेखाकार।<br>(ii) अधीक्षण इंजीनियर/वरिष्ठ कार्य सर्वेक्षक/वरिष्ठ वास्तुविद। |                              |

- |   |   |
|---|---|
| 4. (i) सहायक मण्डल प्रबन्धक/वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक और केन्द्रीय तथा | } |
|   |   |

क्षेत्रीय कार्यालय के सहायक सचिव/सहायक बीमाकर्ता/सहायक लेखाकार। (ii) कार्यपालक इंजीनियर/कार्य सर्वेक्षक/उप वरिष्ठ वास्तुविद।	} 2250-100-3250 रु०

5. (i) शाखा प्रबन्धक/प्रशासनिक अधिकारी (ii) सहायक कार्यपालक इंजीनियर/सहायक कार्य सर्वेक्षक/वास्तुविद	} 1625-100-2925 रु०

6. (i) सहायक शाखा प्रबन्धक/सहायक प्रशासन-अधिकारी (ii) सहायक इंजीनियर/सहायक वास्तुविद।	} 1175-75-1400-85-2675 रु०

टिप्पण :- विभिन्न क्रम संख्याओं के अन्तर्गत प्रसिद्धि (2) में विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्त किए गए अधिकारियों के सम्बन्ध में पृथक वरिष्ठता सूची रखी जाएगी।

5. मंहगाई भत्ता :

(1) श्रेणी 1 अधिकारियों को लागू भत्ते का मापमान निम्नलिखित रूप में अवधारित किया जाएगा :-

(क) सूचकांक : अखिल भारतीय कर्मकार वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (जिसे हमें इसके पश्चात् "सूचकांक" कहा गया है)

(ख) आधार : 1960 की श्रृंखला में सूचकांक सं० 332-100,

(ग) दर : सूचकांक त्रैमासिक औसत में 332 अंकों के ऊपर प्रत्येक आठ अंकों के लिए मूल वेतन का 2 प्रतिशत, किन्तु प्रत्येक आठ अंकों के लिए अधिक से अधिक 31.60 रु० तक (जिसे हमें इसके पश्चात् "विनिर्दिष्ट दर" कहा गया है)।

(2) विनिर्दिष्ट दर पर देय मंहगाई भत्ते का ऊपर की ओर पुनरीक्षण निम्न प्रकार से किया जाएगा :-

(1) प्रत्येक श्रेणी I अधिकारी के लिए जो रु० 1600/- से अधिक मूल वेतन प्राप्त कर रहा है, सूचकांक के त्रैमासिक औसत में 332 अंकों के ऊपर प्रत्येक आठ अंकों की वृद्धि के लिए 332-340-348-356-364-372-380-388-396-404 के क्रम में तथा इसी प्रकार आगे;

(2) रु० 1601 रु० और उससे अधिक किन्तु 2425 रु० से अधिक के मूलवेतन पाने वाले श्रेणी I अधिकारियों के लिए सूचकांक के त्रैमासिक औसत में प्रथम सोलह अंकों की वृद्धि के लिए 332 अंकों के ऊपर 24 अंकों के चक्र में तथा सूचकांक के त्रैमासिक औसत के अगले 8 अंकों की वृद्धि के लिए 332-348-356-372-380-396-404 तथा इसी प्रकार आगे के क्रम में; तथा

(3) 2426 रु० तथा उससे अधिक मूल वेतन पाने वाले श्रेणी I अधिकारियों के लिए सूचकांक के त्रैमासिक औसत में 332 अंकों के ऊपर प्रत्येक 24 अंकों की वृद्धि के लिए 332-356-380-404 तथा इसी प्रकार आगे।

(3) उप नियम (1) या उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) सूचकांक के त्रैमासिक औसत में प्रत्येक 24 बिन्दुओं के चक्र की वृद्धि के लिए मूल वेतन के किसी भी अनुक्रम पर केवल मंह-

गार्ड-भत्ता मूल वेतन के 3.9 प्रतिशत की दर पर देय मंहगाई भत्ते से 150 रु. से जो भी कम हो, कम नहीं होगा; और

(ख) यदि किसी समय उप नियम (2) के अनुसार देय मंहगाई-भत्ता मूल वेतन के किसी भी अनुक्रम निम्नतर मूल वेतन के लिए अनुज्ञेय मंहगाई भत्ते से कम है तो सुसंगत उच्चतर अनुक्रम पर देय मंहगाई भत्ता निम्नतर मूल वेतन पर देय मंहगाई भत्ते के बराबर होगा।

(4) (क) श्रेणी I अधिकारियों का देय मंहगाई-भत्ते का मूल वेतन का संबंधित श्रृंखलाओं में न.च.क. और पुनरक्षण होगा यदि सूचकांक का त्रैमासिक औसत (जिसे इसमें इसके पश्चात् "चापू औसत अंक" कहा गया है) उप नियम (2) में निर्दिष्ट संबंधित क्रम में उस सूचकांक के न.च. गिर जाता है, जिसके प्रति निर्देश से अंतिम पूर्ववर्ती त्रैमास के लिए मंहगाई भत्ते का सदाय किया गया है।

(ख) न.च.क. और पुनरक्षण होने पर, देय मंहगाई-भत्ता चापू औसत अंकों के तत्समान होगा यदि ऐसा चापू औसत अंक सुसंगत श्रृंखला में एक अंक है; तथा देय मंहगाई-भत्ता सुसंगत श्रृंखला में चापू औसत अंक के ठीक प्रथम अंक के तत्समान होगा यदि ऐसा चापू औसत अंक श्रृंखला में एक अंक नहीं है।

6. भत्तान किराया भत्ता:—(1) श्रेणी I अधिकारियों को उनके सिवाय जिन्हें स्टाफ क्वार्टर प्रदायित किया गया है भत्तान किराया भत्ता मूल वेतन के 15% का दर में लागू होगा, किन्तु यह कम से कम 200 रु. तथा अधिकतम 400 रु. होगा।

(2) ऐसे श्रेणी I अधिकार: जिन्हें स्टाफ क्वार्टर प्रदायित किया गया है किस भत्तान किराया भत्ते के हकदार नहीं होंगे, किन्तु वे उन्हें प्रदायित स्टाफ क्वार्टर के लिए मूल वेतन के 10 प्रतिशत या समुचित अनुकूलित शुल्क के समतुल्य रकम का, दोनों में जो भी कम हो, सदाय करेंगे।

7. नगर प्रतिपूरक भत्ता:—श्रेणी 1 के अधिकारियों को वेद नगर प्रतिपूरक भत्ता यह होगा:—

(क) श्रेणी I के अधिकार: को 12 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों में तथा पणजा तथा मामोंगीवा के नगर, य क्षेत्रों में पदस्थ है, मूल वेतन का 10 प्रतिशत, किन्तु अधिक से अधिक 200 रु. प्रति माह, तथा

(ख) श्रेणी I के अधिकार: जो उन नगरों में, जिनका आबादी 5 लाख तथा उससे अधिक किन्तु 12 लाख से कम है तथा राज्यों का राजधानियों में जिनका आबादी 12 लाख से अधिक नहीं है और बण्ड गढ़ पाण्डिचेरी तथा पोर्ट ब्लेयर में पदस्थ है। मूल वेतन का 6 प्रतिशत किन्तु 120 रु. अधिक से अधिक प्रतिमाह।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिये, 1981 का जनगणना का रिपोर्ट में दिए गए आबादी के आंकड़े, गणना से किए जाएंगे।

8. भविष्य निधि:—परिभाषाओं अधिकार: या अस्थायी आधार पर नियुक्त किए गए अधिकार: या किसी अनुसूचित अधिकारिता निधि में अभिदाय कर रहे अधिकार: से निम्न प्रत्येक श्रेणी I अधिकार: निगम द्वारा स्थापित भविष्य निधि में अपने मूल वेतन का 8-1/3 प्रतिशत का दर से अभिदाय करेगा और निगम भी भविष्य निधि में प्रतिमास प्रत्येक अधिकार: द्वारा वस्तुत: अभिवस्त राशि के वास्तविक अभिदान के बराबर रकम का भविष्य निधि में अभिदाय ऐसे प्रत्येक अधिकार: के मूल वेतन का अधिक से अधिक 8-1/3 प्रतिशत तक, करेगा।

(2) प्रोविडेंट गवर्नमेंट मिगोरिट: लाइफ एश्योरेंस कम्पन: लिमिटेड के स्थानान्तरित श्रेणी I अधिकार: और जो उस कम्पन:

की पेंशन निधि में अभिदाय कर रहे हैं, जिसे केवल ऐसे कर्मचारियों के लिए एक पृथक निधि के रूप में, उपनियमों सहित जारी रखा जा रहा है, उस निधि के नियमों के अनुसार पेंशन के हकदार होंगे।

(3) तथापि उपनियम (2) में निर्दिष्ट श्रेणी I के अधिकार:, निगम द्वारा स्थापित भविष्य निधि में अभिदाय करने के लिए अनुज्ञापित किए जा सकते हैं परन्तु ऐसे कर्मचारियों का, बावत भविष्य निधि में निगम से कोई अभिदाय करने का अपेक्षा नहीं होगी।

9. उपदान: (1) (क) ऐसा स्थाय श्रेणी I अधिकार: जो पन्द्रह वर्ष से अल्पतम वर्षों तक (जिसमें 1 सितम्बर, 1956 को या उसके पश्चात् भर्ती किए गए कर्मचारियों का, बावत परिवर्द्धा की या अस्थायी सेवा का अवधि सम्मिलित नहीं का आणी) निगम का निरन्तर सेवा में (जिसमें ब.माकर्ता के पास नियमित वैतनिक सेवा भी सम्मिलित है) रहा है, और:—

(1) जिसका सेवाएं निगम द्वारा किसी भी कारण से समाप्त कर दी जाते हैं, या

(2) जो स्वेच्छा से निगम का सेवा से त्यागपत्र देता है, या

(ख) स्थाय श्रेणी I अधिकार:—

(i) जिसका निगम की सेवा का में रहते हुए मृत्यु हो जाता है, या

(ii) जो निगम का सेवा से सेवा निवृत्त होता है, या

(iii) जिसका सेवाएं या तो निरन्तर न मार के कारण या कित. ऐसा दुर्घटना के कारण जिससे वह अपने कर्तव्यों के निर्वहन में असमर्थ हो जाता है, समाप्त कर दी जाता है; या

(4) जिसका सेवाएं कर्मचार: बृद्ध में कम करने या संस्थापन के पुनर्गठन के कारण समाप्त कर दी जाते हैं; :-

उपदान के सदाय के लिए पात्र होगा।

(2) श्रेणी I के अधिकार: को उपनियम (1) के अधीन अनुज्ञेय उपदान, निरन्तर सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए (जिसमें ब.माकर्ता के पास नियमित वैतनिक सेवा भी सम्मिलित है) एक मास के सेवान्त मूल वेतन की दर से देय होगा किन्तु वह 30 वर्ष का सेवा तक अधिकतम 15 मास के मूल वेतन तथा तथा 30 वर्ष से अधिक का सेवा के लिए सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष या उह मास से अधिक के भाग के लिए आधे मास का सेवान्त मूल वेतन होगा।

परन्तु ऐसे अधिकार: द्वारा अपना सेवा का पूरा अवधि के दौरान 12 मास से अधिक का अवधि तक अमाधारण दुर्घटना पर बिताई गई अवधि अपवर्जित कर दी जाएगी।

(3) ऐसे श्रेणी I अधिकार: की दशा में जिसे श्रेणी 3 के काष्ठर में से पहले, अप्रैल, 1973 को अथवा उसके पश्चात् प्रोन्नत किया गया, तथा जिसका मृत्यु या सेवा निवृत्ति प्रोन्नति के पश्चात् हो जाता है, उसको देय उपदान उम उपदान से कम नहीं होगा जो उसको उस स्थिति में देय होता यदि उसकी सेवा तब समाप्त कर दी जाते जब वह श्रेणी 3 के काष्ठर में था।

(4) श्रेणी I के अधिकार: को अनुज्ञेय उपदान का, रकम पर निगम को प्राप्त किसी धारणाधिकार के अधीन रहते हुए निगम, अधिकार: को, या उसके नाम निर्देशित या नामनिर्देशितियों को, या यदि कोई नामनिर्देशित नहीं किया गया है या विद्यमान नहीं है तो अधिकार: के उत्तराधिकारियों को इस नियम के अधीन अनुज्ञेय उपदान का रकम का संवाय करेगा।

(5) उपर के उपनियमों में अन्तर्निहित किसी बात के होते हुए भी:—

(1) जहाँ श्रेणी 1 के किसी अधिकार: पर प्रबन्धसंग्रह या अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध हिंसा से अन्तर्गत किसी कार्य के विधि या नियोजन के स्थान में या उसके निकट किसी बंगलरूम या

विशुद्ध व्यवहार के लिए पदभ्युक्ति का शास्ति अधिरोपित की जाती है, वहाँ उसे देय उपदान पूर्णतः सम्पन्न हो जाएगा; और

(2) जहाँ श्रेणी I के किसी अधिकारी पर अनिवार्य सेवा निवृत्ति, सेवा में हटाए जाने या पदभ्युक्ति का शास्ति उसके किसी ऐसे कार्य के लिए जिससे निगम को वित्तीय हानि सहना पड़े, अधिरोपित की जाती है वहाँ उसको देय उपदान में उतना रकम सम्पन्न होगी, जितना हानि हुई है।

10 निर्वचन :— यदि इन नियमों के निर्वचन के सम्बन्ध में कोई शंका या कठिनाई उत्पन्न होती है तो उसे विनिश्चय के लिए केन्द्रय सरकार को निविष्ट किया जाएगा।

[फा. सं. 2 (6)/ब. III/85]

ए. सं. मेन, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

Insurance

New Delhi, the 11th October, 1985

### NOTIFICATION

Life Insurance Corporation of India Class I Officers  
(Revision of Terms and Conditions of Service) Rules,  
1985

**GSR 794 (E).**—In exercise of the powers conferred by clause (cc) of sub-section (2) of section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules regulating certain terms and conditions of service of Class I Officers (other than the Managing Directors) of the Life Insurance Corporation of India, namely:—

1. Short title, commencement and application:—

(1) These rules may be called the Life Insurance Corporation of India, Class I Officers (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1985.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of October, 1983.

(3) They shall apply to every whole-time (salaried) Class I Officer of the Corporation in India unless otherwise provided by the terms of any contract.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), Where any Class I Officer gives a notice in writing to the Corporation, within thirty days of the date of publication of these rules in the Official Gazette, expressing his option to be governed by the provisions of these rules with effect from the date of such publication, then the Corporation may, by order, permit such officer to be governed by the said rules with effect from the said date.

2. Definitions:—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956);

(b) "Class I Officer" means an employee of the Life Insurance Corporation of India (other than the Managing Directors) working in Class I post and includes any person who became an employee of Corporation on the appointed day under the Act and is so working;

(c) "Staff Rules" means the Life Insurance Corporation of India (Staff) Regulations, 1960;

(d) words and expressions used in these rules and not defined herein but defined in the Staff Rules, shall have the meanings respectively assigned to them in the Staff Rules.

3. Conditions of Service of Class I Officers: Notwithstanding anything contained in the Staff Rules, the terms and conditions of service of Class I Officers relating to matters covered by these rules shall be regulated in accordance with the provisions hereinafter contained in these rules.

4. Scales of pay of Class I Officers: The scales of pay of Class I Officers shall be as under:—

Class I Officers:

- |   |   |
|---|---|
| 1. (i) Zonal Managers/<br>Chiefs of Departments<br>at Central Office. | (a) Ordinary Scale:<br>Rs. 3725-125-4350  |
| (ii) Chief Engineer/Chief Architect.                                  | (b) Selection Scale:<br>Rs. 4100-125-4600 |

Notes (1) Officers in selection scale posted in-charge of a Department at the Central Office will be designated as Executive Directors.

(2) While Chiefs of Departments at Central Office would normally be drawn from the cadres of Zonal Managers, where suitable officers for filling up these posts are not available from this cadre they may be down from the cadre of Deputy Zonal Managers/Senior Divisional Managers/Secretaries/Actuaries/Accountants at Central Office and they will be designated as Chief-in-Charge.

2. (i) Deputy Zonal Manager/ Senior Divisional Managers and Secretaries/ Actuaries/ Accountants at the Central Office. (ii) Deputy Chief Engineers/ Deputy Chief Architects.	Rs. 3245-110-3685-115-3800.	(ii) Assistant Executive Engineers/ Assistant Surveyors of Works/ Architects.	
3. (i) Divisional Managers and Secretaries/ Actuaries/ Accountants at the Zonal Offices/ Deputy Secretaries (A&I) Deputy Secretaries Deputy Actuaries/- Deputy Accountants at the Central Office. (ii) Superintending Engineers/ Senior Surveyors of Works/ Senior Architects.	Rs. 2715-105-3450.	6. (i) Assistant Branch Managers/ Assistant Administrative Officers. (ii) Assistant Engineers/- Assistant Architects.	Rs. 1175-75-1400-85-2675
4 (i) Assistant Divisional Managers/ Senior Branch Managers and Assistant Secretaries/ Assistant Actuaries/ Assistant Accountants at the Central Office and Zonal Office.	Rs. 2250-100-3250		
(ii) Executive Engineers/ Surveyors of Works/ Deputy Senior Architects.			
5. (i) Branch Managers/ Administrative Officers.	Rs. 1625-100-2725		

Note: A separate seniority list shall be maintained in respect of Officers appointed to posts specified in entry (ii) under various serial numbers.

5. Dearness Allowance: (1) The scales of dearness allowance applicable to Class I Officers shall be determined as under:—

(a) Index: All India Working Class Consumer Price Index (hereinafter referred to as the "Index")

(b) Base: Index No. 332 in the series 1960—100;

(c) Rate: 2 per cent of the basic pay for every eight points in the quarterly average of the Index above 332 points, subject to a maximum of Rs. 31.60 for every 8 points (hereinafter referred to as the "specified rate").

(2) There shall be an upward revision of the dearness allowance payable at the specified rate,—

(i) for every eight points rise in the quarterly average of the Index above 332 points in the sequence 332-340-348-356-364-372-380-388-396-404 and so on, for Class I Officers drawing a basic pay of not more than Rs. 1600/-;

(ii) for the first sixteen points rise in the quarterly average of the Index in a cycle of 24 points rise above 332 points and for the next eight points rise in the quarterly average of the Index in the sequence 332-348-356-372-380-396-404 and so on, for Class I Officers drawing a basic pay of Rs. 1601 and above but not more than Rs. 2425/- and

(iii) for every twenty four points rise in the quarterly average in the Index above 332 points in the sequence 332-356-380-404 and

so on, for those Class I Officers drawing a basic pay of Rs. 2426/- and above.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) or sub-rule (2),—

(a) the dearness allowance payable at any stage of basic pay for each cycle of 24 points rise in the quarterly average of the Index shall not be less than the dearness allowance payable at the rate of 3.9 per cent of the basic pay or Rs. 150/- whichever is less; and

(b) if at any time the dearness allowance payable in accordance with sub-rule (2) at any stage of basic pay is less than that admissible for a lower basic pay, the dearness allowance payable at the relevant higher stage shall be equal to that payable for the lower basic pay.

(4) (a) There shall be downward revision of the dearness allowance payable to Class I Officers in the respective ranges of basic pay if the quarterly average of the index (hereinafter referred to as the "current average figure") falls below the index figure in the respective sequences referred to in sub-rule (2) with reference to which the dearness allowance has been paid for the last preceding quarter.

(b) On the downward revision, the dearness allowance payable shall correspond to the current average figure if such current average figure is a figure in the relevant sequence; and the dearness allowance payable shall correspond to the figure in the relevant sequence next preceding the current average figure if such current average figure is not a figure in the sequence.

6. House Rent Allowance:—(1) The scales of house rent allowance applicable to Class I Officers, except those who have been allotted staff quarters, shall be at the rate of 15 per cent of the basic pay, subject to a minimum of Rs. 200/- and a maximum of Rs. 400/-.

(2) Class I Officers who are allotted staff quarters, shall not be entitled to any house rent allowance but they shall pay an amount equivalent to 10 per cent of the basic pay or the appropriate licence fee, whichever is less, for the staff quarters allotted to them.

7. City Compensatory Allowance: The scales of City Compensatory Allowance payable to Class I Officers shall be as under:—

(a) Class I Officers posted in cities with population exceeding 12 lakhs and Urban Agglomeration of Panaji and Mormugoa—10 per cent of basic pay, subject to a maximum of Rs. 200/- per month; and

(b) Class I Officers posted in cities with a population on 5 lakhs and above but not exceeding 12 lakhs, State Capitals with population not exceeding 12 lakhs and Chandigarh, Pondicherry and Port Blair—6 per cent of basic pay, subject to a maximum of Rs. 120 per month.

Explanation:—For the purposes of this rule, the population figures as reported in the 1981 Census Report shall be taken into account.

8. Provident Fund: (1) Every Class I Officer of the Corporation, other than an Officer on probation or an officer appointed on temporary basis or an officer who is contributing to an approved Superannuation Fund, shall contribute to the Provident Fund established by the Corporation at the rate of  $8\frac{1}{3}$  per cent of his basic pay and the Corporation shall also contribute to the Provident Fund every month an amount equal to the actual contribution of each such officer subject to a maximum of  $8\frac{1}{3}$  per cent of the basic pay of each such officer.

(2) Class I Officers who are transferred employees of the Oriental Government Security Life Assurance Company Ltd., and who are contributing to the Pension Fund of that Company, which is being continued with modifications as a separate Fund for such employees only, shall be entitled to pension according to the rules of that Fund.

(3) Class I Officers referred to in sub-rule (2) may, however, be permitted to contribute to the Provident Fund established by the Corporation but the Corporation shall not be required to make any contribution to the Provident Fund in respect of such officers.

9. Gratuity: (1) (a) A permanent Class I Officer who has been in continuous service of the Corporation (including regular salaried service with the insurer for not less than 15 years (excluding period of probation or temporary service in respect of employees recruited on or after the 1st September, 1956); and—

(i) whose services are terminated by the Corporation for any reason whatsoever; or

(ii) who voluntarily resigns from the service of the Corporation;

or

(b) a permanent Class I Officers

(i) who dies while in the service of the Corporation;

or

(ii) who retires from the service of the Corporation;

or

- (iii) whose services are determined either due to continued illness or accident incapacitating him from the proper discharge of his duties;

or

- (iv) whose services are dispensed with owing to reduction of staff or reorganisation of establishment;

shall be eligible for the payment of gratuity.

(2) The gratuity admissible to a Class I Officer under sub-rule (1) shall be at the rate of one month's terminal basic pay for each completed year of continuous service or part thereof in excess of six months (inclusive of regular salaried service with the insurer) subject to a maximum of 15 months' basic pay upto 30 years of service, and for service over 30 years, half-a-month's terminal basic pay for each completed year of service or part thereof in excess of six months:

Provided that any period spent by such officer on extraordinary leave exceeding 12 months during the entire period of his service shall be excluded.

(3) In the case of a Class I Officer who has been promoted from Class III cadre on or after the 1st day of April, 1973 and who dies or retires after promotion, the Gratuity payable to him shall not be less than the gratuity that would have been payable to him if his services had been terminated while he was in Class III cadre.

(4) Subject to any lien the Corporation may have on the amount of gratuity admissible to a Class I Officer, the Corporation shall pay the Officer or his nominee or nominees or if no nomination is made or is subsisting, his heirs, the amount of gratuity admissible under this rule.

(b) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-rules—

- (i) where the penalty of dismissal is imposed on a Class I Officer for any act involving violence against the management or other employees or any riotous or disorderly behaviour in or near the place of employment, the gratuity payable to him shall stand wholly forfeited;

and

- (ii) where the penalty of compulsory retirement removal from service or dismissal is imposed on a Class I Officer for any act involving the Corporation in financial loss, the gratuity payable to him shall stand forfeited to the extent of such loss.

10. Interpretation: Where any doubt or difficulty arises as to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Central Government for its decision.

[F.No.2(6)/Ins.III/85]  
A.C. SEN, Jt. Secy.

